भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 710

24 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

अमृत योजना के अंतर्गत बजट आवंटन

710. श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के झुंझुनू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पिछले दस वर्षों के दौरान पेयजल, सीवरेज, पार्क, सड़कें और एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग जैसी मूलभूत शहरी अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) के अंतर्गत बहुत कम/सीमित बजट आवंटन किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए उक्त मिशन के अंतर्गत अब तक आवंटित बजट का स्थानवार ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त अवधि के दौरान पूरे किए गए कार्यों के साथ-साथ पूरा होने के लिए लंबित कार्यों का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 25 जून 2015 को देश भर के 500 चयनित शहरों (15 विलयित शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में शुरू किया गया था। यह मिशन चयनित शहरों और कस्बों में जल आपूर्ति; सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन; वर्षा जल निकासी; हरित क्षेत्रों और पार्कों; और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित है।

अमृत के अंतर्गत, केंद्रीय निधियाँ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को आवंटित/जारी की जाती हैं और निधियां शहरों/यूएलबी को नहीं जारी की जातीं। अमृत के अंतर्गत, राजस्थान राज्य का अनुमोदित योजना आकार 3,223.94 करोड़ रुपये है जिसमें 1,541.95 करोड़ रुपये का प्रतिबद्ध केंद्रीय हिस्सा शामिल है, जिसमें से 1,511.23 करोड़ रुपये राज्य सरकार को जारी किए जा चुके हैं।

अमृत के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को परियोजनाओं के चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन का अधिकार दिया गया है। शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी), राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित करने, निगरानी करने और पर्यवेक्षण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती है। एसएचपीएससी की सिफारिश पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) की शीर्ष समिति मिशन के व्यापक फ्रेमवर्क के भीतर परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करती है।

अमृत के अंतर्गत, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अमृत पोर्टल पर बताया गया है, झुंझुनू शहर ने 8.44 करोड़ रुपये की लागत की 04 परियोजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें 6.99 करोड़ रुपये की एक जल निकासी परियोजना और 1.45 करोड़ रुपये की लागत की 03 हरित क्षेत्र एवं पार्क परियोजनाएँ शामिल हैं। सभी 04 परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं।

******